MODEL ANSWER

Q. India's forest and tree cover has increased to 25.17% as per the ISFR 2023. However, challenges such as declining mangrove cover, forest degradation, and loss of biodiversity persist. Discuss the steps that can be taken to further enhance and sustainably manage India's green cover

India's green cover is vital for its ecological balance and socio-econoic development. As per the India State of Forest Report (ISFR) 2023, the country has made incremental progress in forest and tree cover, reflecting efforts toward sustainable environmental management. However, the challenges demand a strategic approach to enhance and conserve these resources.

The ISFR 2023 reveals that India's forest cover has reached 21.76%, while the tree cover stands at 3.41%, resulting in a total green cover of 25.17% of the country's geographical area. Despite a net increase of 156.41 sq km in forest cover and 1,285.4 sq km in tree cover since 2021, issues persist. Moderately dense forests decreased by 1,234.95 sq km, and open forests by 1,189.27 sq km, indicating forest degradation. Mangrove cover saw a decline of 7.43 sq km, with Gujarat witnessing the highest loss. The Western Ghats and Northeastern states recorded significant forest cover reductions, posing ecological risks. Such challenges highlight the urgent need for sustainable forest management.

Steps to Enhance and Sustainably Manage Green Cover

1. Implementation of Central Initiatives:

- **Green India Mission (GIM):** Strengthening of afforestation activities under GIM is needed. The mission has already supported efforts with Rs. 755.28 crores allocated to 17 states and one UT.
- **Nagar Van Yojana (NVY):** the creation of Nagar Vans and Nagar Vatikas in urban areas needs to be accelerated to preserve biodiversity and enhance urban green spaces.
- **Compensatory Afforestation Fund (CAMPA):** optimal utilization of CAMPA funds needs to be ensured to offset forest land diversion for developmental projects.

2. Promotion of Community-Based Afforestation:

- It is important to involve local communities through the **Joint Forest Management (JFM)** framework and schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
- Missions such as **Sub-Mission on Agroforestry** and **National Bamboo Mission** to promote sustainable livelihoods and expand tree cover needs to be encouraged.

3. Policy and Climate Integration:

- Implementing the **Draft National Forest Policy**, focusing on climate change mitigation and involving the forest-dependent communities in the process is necessary.
- Forest conservation needs to be aligned with India's Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

4. Technology and Research:

- It is important to promote the use of geospatial technologies, drones, and AI for precise monitoring and early intervention in degraded forest areas.
- Investment in research for the restoration of mangroves and other fragile ecosystems is need of the hour.

5. Multi-Stakeholder Approach:

- Collaborations with State Governments, NGOs, corporate entities, and civil society needs to be fostered to amplify conservation efforts.

Sustainable forest management is integral to India's ecological and socio-economic well-being. By scaling initiatives like GIM and NVY and addressing gaps in conservation, India can not only

enhance its green cover but also meet global climate commitments, ensuring a resilient future for its ecosystems and communities.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न. "आईएसएफआर 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर 25.17% हो गया है। हालांकि, मैंग्रोव कवर में गिरावट, वन क्षरण और जैव विविधता की हानि जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भारत के हरित आवरण को और बढ़ाने और उसे स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करें।

भारत का हरित क्षेत्र इसके पारिस्थितिक संतुलन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, देश ने वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धिशील प्रगति की है, जो सतत पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में प्रयासों को दर्शाता है। हालाँकि, इन संसाधनों को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, भारत का कुल वनावरण 21.76% तक पहुँच गया है, जबकि वृक्ष आवरण 3.41% है, जिसके परिणामस्वरूप देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल हरित क्षेत्र 25.17% हो गया है। 2021 से वन क्षेत्र में 156.41 वर्ग किमी और वृक्ष क्षेत्र में 1,285.4 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि के बावजूद, कुछ समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। मध्यम घने वनों में 1,234.95 वर्ग किमी और खुले वनों में 1,189.27 वर्ग किमी की कमी आई है, जो वन क्षरण को दर्शाता है। मैंग्रोव कवर में 7.43 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक नुकसान हुआ। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में वनावरण में काफी कमी दर्ज की गई, जिससे पारिस्थितिकी जोखिम पैदा हुआ। ऐसी चुनौतियाँ टिकाऊ वन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

हरित आवरण को बढ़ाने और सतत रूप से प्रबंधित करने के लिए कदम

1. केंद्रीय पहलों का कार्यान्वयन:
    a. **हरित भारत मिशन (जीआईएम):** इस प्रकार के मिशन के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियों को मजबूत करना चाहिए। मिशन ने पहले ही 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 755.28 करोड़ रुपये आवंटित करके प्रयासों का समर्थन किया है।
    b. **नगर वन योजना:** जैव विविधता को संरक्षित करने और शहरी हरित स्थानों को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में नगर वन और नगर वाटिकाओं के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता है।
    c. **प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAMPA):** विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को संतुलित करने के लिए CAMPA निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. **समुदाय-आधारित वनीकरण को बढ़ावा देना:**
    a. संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) ढांचे और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
    b. स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और वृक्ष आवरण का विस्तार करने के लिए कृषि वानिकी पर उप-मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे मिशनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. **नीति और जलवायु एकीकरण:**
    a. जलवायु परिवर्तन शमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे को लागू करना और वन-आश्रित समुदायों की मदद लेना आवश्यक है।
    b. वन संरक्षण को पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
4. **प्रौद्योगिकी और अनुसंधान:**
    a. क्षीण वन क्षेत्रों में सटीक निगरानी और प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, ड्रोन और एआई के उपयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
    b. मैंग्रोव और अन्य नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली के लिए अनुसंधान में निवेश समय की मांग है।
5. **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:**
    a. संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सतत वन प्रबंधन भारत के पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक कल्याण का अभिन्न अंग है। हरित भारत मिशन और नगर वन योजना जैसी पहलों को आगे बढ़ाकर और संरक्षण में मौजूदा खामियों को दूर करके, भारत न केवल अपने हरित

आवरण को बढ़ा सकता है, बल्कि वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकता है, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों के लिए एक सतत एवं उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके।

Samyak
An Institute For Civil Services